माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के समक्ष

रिखी राम बनारसी दास-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 316 1977 दिसंबर 10, 1984

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का XI) (हरियाणा राज्य पर लागू) - धारा 10, 39 और 40 - कर निर्धारण प्राधिकारी एक अतिरिक्त मांग बना रहा है और कर का भुगतान न करने पर जुर्माना लगा रहा है - निर्धारिती ने आदेश को अपील में सफलतापूर्वक चुनौती दी है जुर्माना लगाना– ट्रिब्यूनल द्वारा अपील में अपीलीय आदेश को बरकरार रखा गया–आयुक्त ने धारा 40 के तहत अपीलीय आदेश को संशोधित करने की मांग की–विलय का सिद्धांत–चाहे लागू हो–आयुक्त–क्या अपीलीय आदेश को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र है।

माना गया कि पंजाब जनरल सेल्स-टैक्स एक्ट, 1948 की धारा 39(2) की भाषा से यह स्पष्ट है कि एक अपीलीय आदेश ट्रिब्यूनल में अपील योग्य है। अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) से यह समान रूप से स्पष्ट है कि उपधारा (2) के तहत अपील पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित प्रत्येक आदेश धारा 42 के प्रावधानों के अधीन अंतिम होगा। ट्रिब्यूनल की व्यापक शक्तियों को धारा 39 की उप-धारा (6) में वर्णित किया गया है और यह शक्ति आदेश के उचित और उचित होने के अधीन पूर्ण है। इस शक्ति में कर या जुर्माना या ब्याज या सभी की राशि को बढ़ाना शामिल है। शक्ति की समावेशी प्रकृति किसी भी तरह से इसे कम नहीं करती, बल्कि इसके परिमाण को दर्शाती है। चीजों की उपयुक्तता में ऐसा ही होना चाहिए। जब अपीलीय आदेश आगे अपील के लिए ट्रिब्यूनल में जाता है और अनिवार्य रूप से निर्धारिती के कहने पर, ट्रिब्यूनल

के पास उस पर ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति होती है, जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझता है, जिसमें ऐसे आदेश भी शामिल हैं जो निर्धारिती के खिलाफ जा सकते हैं।

चूंकि किसी न किसी कारण से. उसने ऐसा नहीं किया, यह नहीं बताया जाएगा

धारा 39 की उपधारा (4) के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश की अंतिमता पर। स्पष्ट विधायी इरादे में एक उद्देश्य है कि आयुक्त को एक साथ पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान किए जाने की उपस्थिति में उस आदेश को अंतिम रूप दिया जाए। आयुक्त की पुनरीक्षण की शक्ति अधिनियम की धारा 40 के तहत आयुक्त की शक्ति को दरकिनार करते हुए, ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी मूल्यांकन प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहले से लंबित या निपटाए गए किसी भी मामले के रिकॉर्ड को मांगने तक फैली हुई है। ताकि ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के आदेशों को उसके दायरे से दूर रखा जा सके। और ट्रिब्यूनल के आदेश को स्पष्ट रूप से अंतिम बनाना, विधानमंडल के इरादे को स्पष्ट करता है कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के साथ आयुक्त द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जानी थी; क्योंकि जो काम सीधे तौर पर करने से मना किया गया है उसे अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रत्यक्ष दलील के आधार पर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन अकेले अपीलीय आदेश को संशोधित करने की मांग की जा रही है। ऐसे पाठ्यक्रम की अनुमति देना क़ानून के साथ धोखाधड़ी होगी: यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। चीजों की योजना और उपरोक्त प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा में, विलय का सिद्धांत ट्रिब्यूनल के आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश को भी कवर करने और एक सुरक्षात्मक छतरी देने के लिए सामने आता है, जब वह पहले अपीलीय मिल से गुजर चुका हो। न्यायाधिकरण. इस प्रकार, इन कारणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आयुक्त के पास अपीलीय आदेश को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, चाहे बाद वाला आदेश कितना भी गलत क्यों न हो और आयुक्त मामले के गुण-दोष के आधार पर कितना भी उचित क्यों न हो।

(पैरा 3).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(ए) हरियाणा अधिनियम की धारा 40 को पूर्वव्यापी प्रभाव से असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है;

(बी) आदेश अनुलग्नक पी-3 को गैरकानूनी और क्षेत्राधिकार के बिना, सर्टिओरीरी की रिट जारी करके रद्द किया जा सकता है;

(सी) अनुबंध पी-3 द्वारा बनाई गई मांग और वसूली पर इस रिट याचिका के निर्णय तक रोक लगाई जा सकती है।

(डी) याचिकाकर्ता को ऐसी अन्य अंतरिम और/या अंतिम राहत दी जा सकती है जो आपके आधिपत्य को मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत, उपयुक्त और उचित प्रतीत हो;

(ई) मामले के रिकॉर्ड को तलब करने का आदेश दिया जा सकता है।

(एफ) अनुबंध "पी-1 से पी-3" की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की छूट दी जाए;

(छ) इस याचिका की लागत भी उत्तरदाताओं के विरुद्ध याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

1984 का सिविल विविध क्रमांक 1578।

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना है कि तय तिथि पर मामले की सुनवाई के लिए रिकार्ड तलब किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर. सी. डोगरा।

मुनेश्वर पुरी, वकील, ए.जी. हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

माननीय न्यायाधीश एम. एम. पुंछी (मौखिक)-

(1) आयुक्त ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 40 के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) के एक अपीलीय आदेश को उस समय संशोधित किया जब बाद के आदेश दूसरी अपील में बिक्री-कर न्यायाधिकरण की जांच में खरा उतरा था। इस संबंध में विचार के लिए कानून का मुद्दा यह है कि क्या विलय का सिद्धांत लागू होगा और उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) के अपीलीय आदेश को अधिनियम की धारा 40 के तहत चुनौती से मुक्त रखा जाएगा या आयुक्त है उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) के आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं?

(2) संक्षेप में कहा गया है, याचिकाकर्ता एक साझेदारी संस्था है जो कालांवाली, तहसील और जिला सिरसा में कमीशन एजेंसी का व्यवसाय करती है। निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए, मूल्यांकन प्राधिकारी ने मूल्यांकन तैयार करते समय रुपये से अधिक की अतिरिक्त मांग बनाई। 36,000 रुपये का कर का भुगतान न करने पर जुर्माना लगाया गया। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (हरियाणा राज्य पर लागू) की धारा 10(6) के तहत 5,000। वह आदेश याचिका का अनुलग्नक पी-1 है। याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक अपील की और आदेश अनुलग्नक पी-2 के तहत जुर्माना रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने क्वांटम पक्ष पर ट्रिब्यूनल के समक्ष दूसरी अपील में मामले को आगे बढ़ाया और आदेश बरकरार रखा गया। ऐसी घटना के बाद, आयुक्त ने अधिनियम की धारा 40 के तहत अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, याचिकाकर्ता को 21 मई, 1976 को उनके सामने पेश होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिससे उनका इरादा जाहिर हुआ कि वह उप उत्पाद शुल्क के आदेश को संशोधित करना चाहते हैं और कराधान आयुक्त (अपील) (अनुलग्नक पी-2)। याचिकाकर्ता के विरोध के बावजूद, आदेश को संशोधित किया गया क्योंकि उसमें एक त्रुटि पाई गई, कि उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) ने धारा 10(7) के तहत जुर्माना नहीं लगाया था। उस परिसर पर रु. आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता पर पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (हरियाणा राज्य पर लागू) की धारा 10(7) के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता

ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से सीधे इस न्यायालय से संपर्क किया, जिसमें अधिनियम की धारा 40 की संवैधानिकता के साथ-साथ आदेश अनुबंध पी-3 को भी चुनौती दी गई। इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रश्न का निपटारा किए जाने के मद्देनजर अधिनियम की धारा 40 को चुनौती देना अब उपलब्ध नहीं है, याचिकाकर्ता ने अब विभिन्न आधारों पर अपने हमले को आदेश तक सीमित कर दिया है, लेकिन इस याचिका के निपटान के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए केवल एक से निपटने की जरूरत है।

(3) अधिनियम की धारा 39(2) की भाषा से यह स्पष्ट है कि उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) का एक अपीलीय आदेश आगे ट्रिब्यूनल में अपील करने योग्य है। अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) से यह समान रूप से स्पष्ट है कि उपधारा (2) के तहत अपील पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, धारा 42 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम होगा। ट्रिब्यूनल की व्यापक शक्तियों को धारा 39 की उपधारा (6) में नीचे दिए गए शब्दों में वर्णित किया गया है: -

"...एक अपीलीय प्राधिकारी अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है

न्यायसंगत और उचित माना जाता है, जिसमें इस अधिनियम के तहत कर या जुर्माना या ब्याज या सभी की राशि बढ़ाने का आदेश, या निर्धारित कर या लगाए गए जुर्माना या लगाए गए ब्याज या सभी की वसूली पर रोक लगाने वाला आदेश शामिल है;"

शक्ति शर्तों में पूर्ण है, बशर्ते कि आदेश न्यायसंगत और उचित हो। इस शक्ति में कर या जुर्माना या ब्याज या सभी की राशि बढ़ाना शामिल है। शक्ति की समावेशी प्रकृति किसी भी तरह से इसे कम नहीं करती, बल्कि इसके परिमाण को दर्शाती है। चीजों की उपयुक्तता में ऐसा ही होना चाहिए। जब उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त का अपीलीय आदेश ट्रिब्यूनल में आगे की अपील में जाता है और आवश्यक रूप से निर्धारिती के कहने पर, ट्रिब्यूनल के पास उस पर ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति होती है, जैसा कि वह उचित और उचित समझता है, जिसमें ऐसे आदेश भी शामिल हैं जो लागू हो सकते हैं। निर्धारिती के

विरुद्ध जाना। यदि ट्रिब्यूनल ने धारा 10(7) के तहत निर्धारिती पर जुर्माना लगाने में विफलता के लिए उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि देखी होती, तो ट्रिब्यूनल अभी भी इस तरह का जुर्माना लगाने के अपने अधिकार में था। चूँकि किसी न किसी कारण से, उसने ऐसा नहीं किया, इससे धारा 39 की उपधारा (4) के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश की अंतिमता के बारे में पता नहीं चलेगा। उस आदेश के लिए स्पष्ट विधायी इरादे में एक उद्देश्य है आयुक्त को एक साथ पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान किए जाने की उपस्थिति में अंतिम रूप दिया जाएगा। आयुक्त की पुनरीक्षण की शक्ति ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी मूल्यांकन प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित या निपटाए गए किसी भी मामले के रिकॉर्ड को मांगने तक फैली हुई है। सत्ता को दरकिनार करना अधिनियम की धारा 40 के तहत आयुक्त का, ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के आदेशों को उसके दायरे से दूर रखना, और ट्रिब्यूनल के आदेश को स्पष्ट रूप से अंतिम बनाना, विधानमंडल की मंशा को स्पष्ट करता है कि ट्रिब्यूनल के आदेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी। आयुक्त द्वारा छेड़छाड़ की जाएगी; क्योंकि जो काम सीधे तौर पर करने से मना किया गया है, उसे इस स्पष्ट दलील के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन अकेले उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के आदेश को संशोधित करने की मांग की जा रही है। इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देना, जैसा कि मुझे लगता है, क़ानून के साथ धोखाधड़ी होगी: एक ऐसा पाठ्यक्रम जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उपरोक्त प्रावधानों में नियोजित चीजों और भाषा की योजना में, विलय का सिद्धांत ट्रिब्यूनल के आदेश के साथ-साथ उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के आदेश को कवर करने और एक सुरक्षात्मक छतरी देने के लिए सामने आता है। ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलीय मिल। इस प्रकार, इन कारणों से मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आयुक्त के पास उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के आदेश को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, भले ही बाद वाला आदेश कितना भी गलत क्यों न हो और आयुक्त को मामले के गुण-दोष के आधार पर कितना भी दोषी क्यों न ठहराया गया हो।

(4) प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है अर्थात याचिकाकर्ता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध। इस प्रकार, आयुक्त का आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर ध्यान दिए बिना रद्द किया जाना चाहिए। यह याचिका तदनुसार सफल होती है लेकिन लागत के संबंध में किसी आदेश के बिना। 1984 का सिविल विविध क्रमांक 1578 निरर्थक हो गया है और उसे ऐसे ही खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा